जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर
Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 31 संख्याः 247 प्रभात उदयपुर, बुधवार 10 जुलाई, 2024 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भजनलाल सरकार का पहला बजट आज दिया कुमारी पेश करेंगी

गत चार सरकारों के कार्यकाल के बाद पहला मौका है जब राज्य सरकार केन्द्र से पहले बजट पेश कर रही है

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री कार्यालय में मु.मंत्री भजनलाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा के साथ मिलकर बजट को अंतिम रूप दिया। दीया कुमारी बुधवार सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2024-25 का नया परिवर्तित बजट विधानसभा में पेश करेंगी।

- वर्ष 2004, 2009, 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब केन्द्र के बजट के बाद राज्य सरकार का बजट आया था, पर इस बार राज्य सरकार पहले बजट पेश कर रही है।
- गत साल दिसम्बर में बनी भजनलाल शर्मा की सरकार ने फरवरी में लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र पूर्ण बजट की बजाय चार माह का लेखानुदान पेश किया था जिसकी अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही है।
- समझा जाता है कि बजट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा वित्तमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री ने अलग-अलग वर्गों के साथ जो चर्चाएं की थीं उसकी झलक बजट में नज़र आएगी।

जयपुर, 9 जुलाई (का.सं.)। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान सरकार का वर्ष 2024-25 का परिवर्तित बजट बुधवार को विधानसभा में पेश करेंगी। बजट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। दीया कुमारी ने वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अखिल अरोड़ा, वित्त विभाग (बजट) शासन सचिव देवाशीष पृष्टी, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्ण कान्त पाठक, शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश ठकराल और निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा के साथ मंगलवार को राज्य के वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट को अंतिम रूप दिया। बुधवार सुबह 11 बजे वित्त मंत्री के तौर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी बजट पेश करेंगी।

पिछली चार सरकार के कार्यकाल को देखें तो यह पहला मौका है जब राज्य सरकार केंद्र सरकार से पहले बजट पेश करेगी। वर्ष 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब केन्द्र का बजट 8 जुलाई को तो राज्य का बजट 12 जुलाई को पेश हुआ था। इसी तरह 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद भी केन्द्र का बजट 6 जुलाई को तो राज्य का बजट 8 जुलाई को पेश हुआ। वर्ष 2014 में केन्द्र का बजट 10 जुलाई को तो राज्य का बजट 14 जुलाई को और 2019 में केन्द्र का बजट 5 जुलाई को तो राज्य का बजट 10 जुलाई को आया था। लेकिन 2024 में अभी तक केन्द्र का बजट नहीं आया लेकिन उससे पहले राज्य सरकार की ओर से बजट लाया जाएगा।

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में बनी भजनलाल सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। इससे पहले फरवरी में सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लेखानुदान पेश किया था। यह लेखानुदान 4 महीने के लिए लाया गया था, लेखानुदान की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। ऐसे में सरकार 10 जुलाई

(शेष पृष्ठ 5 पर)

नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की सजा

जयपुर, 9 जुलाई। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग लड़की से ज्यादती करने वाले अभियुक्त रामस्वरूप को बीस साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर

- केस में पीड़िता और उसके माता-पिता ने दुष्कर्म से इन्कार कर दिया था, पर, डी.एन.ए. रिपोर्ट्स के आधार पर पुनः अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया तथा 1.02 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बधाई दी

जयपुर, 9 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द एपोस्टल से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी उनका योगदान अतुलनीय है। उन्हें प्रदान किया गया यह सम्मान विश्व बिरादरी में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है।

कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा में लायेगी

हाईकमान ने तेलंगाना के मु.मंत्री को आदेश दिया था कि कांग्रेस के युवा सांसद अनिल यादव से राज्यसभा से इस्तीफा लेकर, अनिल यादव के स्थान पर अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा की सदस्यता दिलवायें

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- तेलंगाना के मु.मंत्री रैवन्त रेड्डी ने होशियारी से राजनीतिक पत्ते खेलते हाईकमान की इच्छा भी पूरी कर दी तथा नज़दीकी मित्र व वफादार अनिल यादव को बलि होने से भी बचा लिया।
- मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी ने तेलंगाना के पुराने कांग्रेसी नेता केशव राव, जो कि टी.आर.एस. के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के प्रभाव में आकर कांग्रेस छोड़ टी.आर.एस. में शामिल हो गए थे तथा राज्यसभा सदस्य भी थे, को पुनः कांग्रेस जॉइन करवाई तथा उनसे राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया।
- केशव राव के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सदस्य बनाने की तैयारी है।

नई दिल्ली, 9 जुलाई। जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा में लाया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी से कहा था कि वे अभिषेक मनु सिंघवी को अपने राज्य से राज्यसभा में लाए। रेड्डी को कहा गया था कि उन्हें युवा सांसद अनिल यादव का इस्तीफा लेना है और उनकी जगह सिंघवी को राज्यसभा में लाना है। रैवन्त रेड्डी ने इसके लिए कुछ समय मांगा था।

अनिल यादव मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं और मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि वे अपने पद से इस्तीफा दें। इसलिए उन्होंने बी.आर.एस. के सीनियर नेता केशव राव को कांग्रेस में शामिल होने के लिए राजी किया। राव ने उनकी बात मानी और मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी की उपस्थिति में वे कांग्रेस में शामिल हो गए।

केशव राव कांग्रेस के पुराने आदमी रहे हैं। वह पार्टी छोड़कर चन्द्रशेखर राव की तत्कालीन टी.आर.एस. और अब बी.आर.एस. में शामिल हो गए थे।

केशव राव ने अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। अब इस सीट पर उपचुनाव होगा, जिसके जरिए अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में लाया जाएगा। केशव राव को मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में हैदराबाद में ही एडजस्ट किया जा रहा है।

रैवन्त रेड्डी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उन्हे अपने युवा करीबी सहयोगी का बलिदान नहीं करना पड़ा। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में एडजस्ट करने पार्टी नेतृत्व के निर्देश की पालना की और केशव राव को कांग्रेस में शामिल कर राज्यसभा में पार्टी की सीटें भी बढ़ा लीं।

सूत्र कहते है कि सिंघवी कई अन्य राजनीतिक पार्टियों और राज्यों के माध्यम से राज्यसभा में एडजस्ट किए जा सकते थे, लेकिन ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस चाहती थी कि सिंघवी उनकी पार्टी से राज्यसभा में जाए क्योंकि वे पार्टी के लिए कई कानूनी लड़ाइयां लड़ते रहे हैं।

स्मरण रहे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागियों के वोट भाजपा खेमें में शिफ्ट हो जाने के कारण सिंघवी वहां से राज्यसभा चुनाव हार गए थे।

चार दिन में दूसरी बार राहुल गांधी यू.पी. जा रहे हैं

यू.पी. को इतना महत्व इसलिये दे रहे हैं राहुल, क्योंकि यू.पी. में निकट भविष्य में दस उपचुनाव (बाय इलैक्शन) हैं तथा इण्डिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में यू.पी. में मिली भारी सफलता का क्रम (मोमैन्टम) जारी रखना चाहता है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रायबरेली यात्रा पिछले चार दिनों में उनकी दूसरी उत्तरप्रदेश यात्रा है। राहुल की इन यात्राओं को इंडिया ब्लॉक की इन योजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है कि राज्य की 10 विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उपचुनावों के लिये लोकसभा चुनावों के माहौल को बरकरार रखा जाये। राहुल शुक्रवार को हाथरस गये थे तथा भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से मिले थे।

इन उपचुनावों को कराये जाने का कारण यह है कि सम्बन्धित सीटों के विधायक सांसद चुन लिये गये हैं। इसके

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- इन दस उपचुनावों में से पांच पर गत विधानसभा में भाजपा व सहयोगी पार्टियाँ जीतीं थीं, तथा शेष पांच पर, इण्डिया गठबंधन का कब्जा था।
- राहुल गांधी, सपा नेता को प्रस्ताव देना चाहते हैं कि जिन सीटों पर सपा का कब्जा था, सपा उन पर जरूर चुनाव लड़े, पर, बाकी तीन चार सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने दे।
- इन उपचुनावों के नतीजों का, योगी सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर, अगर इण्डिया गठबंधन ज्यादा सीटें जीतती है तो, इण्डिया गठबंधन के मनोबल पर भारी प्रभाव पड़ेगा। यह बात भाजपा पर लागू होती, विशेषकर मिल्कीपुर सीट की जीत-हार भाजपा के लिये बहुत प्रतीकात्मक महत्व रखती है।

ए.डी.जे. भर्ती केस, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की एस.एल.पी. खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने

जयपुर, 9 जुलाई (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने एडीजे भर्ती-2020 में वकील कोटे के 85 रिक्त पदों पर केवल चार अभ्यर्थियों को ही पद पर नियुक्ति के लिए चयनित करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के 14 फरवरी 2024 के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार परीक्षा की ओर से पेश स्पेशल लीव पैटीशन (एस.एल.पी.) प्रारंभिक सुनवाई के स्तर पर ही खारिज कर दी।

- हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने हाई कोर्ट द्वारा ए.डी.जे. भर्ती परीक्षा में कानूनविदों व प्रोफेसरों की कमेटी बनाए जाने के आदेश का विरोध किया था।

दरअसल हाईकोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ए.डी.जे. भर्ती परीक्षा को

(शेष पृष्ठ 5 पर)

भारत-रूस संवाद से पहले प्र.मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया

यह एक अनायास, यूँ ही हो जाने वाला कृत्य नहीं था, वरन इसमें कई मैसेज छुपे थे तथा सोची समझी विदेश नीति के अनुरूप उठाया गया कदम था

-अंजर रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जुलाई। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मॉस्को में होने वाली वार्ता से पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से गले मिले तथा इस प्रकार भारत ने पावर डिप्लोमेसी की दिशा में अपने कदम बढ़ाये। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसकी कटु आलोचना की है। पश्चिमी देश, जो रूस और पुतिन को अलग-थलग डाल देना चाहते हैं, भी भारत के इस प्रयास के घोर आलोचक हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ैलैंस्की ने भारत की कठोर आलोचना की है तथा कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र को दुनिया के निकृष्टतम "अपराधी एवं तानाशाह" से गले मिलते हुये देखना बहुत तकलीफदेह है।

मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा का समर्थन एवं बचाव सैद्धान्तिक आधार पर शायद ही किया जा सके। आखिर रूस ने एक सम्प्रभुता-सम्पन्न देश पर हमला किया तथा आज भी उस देश की जमीन युद्धरत है। भारत सभी देशों की सम्प्रभुता एवं उनकी क्षेत्रीय अखंडता के लिये यू.एन.चार्टर का पूरी तरह समर्थन करता है। भारत अन्य देशों के क्षेत्र पर इस प्रकार के सभी आक्रमणों का भी विरोध करता है।

लेकिन फिर भी, भारत के सम्मुख ऐसे बहुत अधिक कूटनीतिक तथा वास्तविक राजनयिक लक्ष्य हैं जिनके चलते उसे रूस के साथ अपने परम्परागत एवं अच्छे सम्बन्धों को आगे बढ़ाना ही है। तथापि, भारत को अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति की मुद्रा को भी बनाये रखना होता है।

भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह रूस की यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश का समर्थन नहीं करता भारत ने अपना पूर्व रुख दोहराते हुए रूस से आग्रह किया था कि वे यूक्रेन में युद्ध बन्द कर दें।

भारत-रूस मित्रता रूस के साथ स्थायी सम्बन्ध बनाये रखना भारत के बहुत पुराने तथा सतत हितों की दिशा में उठाया गया एक और और कदम है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- पहली बात तो भारत यह मैसेज देना चाहता था कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति के तहत काम करता है तथा किसी खेमे या ग्रुप से बंधा नहीं है।
- यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ैलैन्सकी तथा पश्चिमी देशों ने मोदी की, गले लगने की बात की जमकर निंदा की।
- शायद सिद्धांत की बात की जाये तो भारत को रूस के नजदीक दिखने का कोई "डिफैन्स" नहीं हो सकता, पर, भारत के जमीनी हालात, जैसे रूस पर पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से खूब पैट्रोलियम खरीदा वह भी डिस्काउन्ट पर और भारत रूस से शस्त्र खरीदते रहना चाहता है।

सचिन पायलट ने टोंक जिले के भांची गाँव पहुँचकर पुलिसकर्मी खुशीराम बैरवा की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की

टोंक में ही पायलट ने बालिका सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के नवीन भवन का लोकार्पण किया

टोंक, 9 जुलाई (निसं)। पूर्व उपमुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने मंगलवार को जिले के देवली भांची गांव में, पुलिसकर्मी कान्स्टेबल खुशीराम बैरवा की मौत पर संवेदना व्यक्त की तथा परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। ज्ञातव्य है कि कान्स्टेबल खुशीराम बैरवा की गत दिनों अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पायलट ने टोंक शहर में राजकीय बालिका सीनियर सैंकेंडरी स्कूल कोहना के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पायलट ने कहा कि सरकार या जनप्रतिनिधि या किसी के भी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी पैसा व्यय किया जाता है, वह एक प्रकार का निवेश है।

इस दौरान पायलट ने कहा कि बॉर्डर पर स्थिति ठीक नहीं है, जवान शहीद हो रहे हैं। सीमापार से हमले हो रहे हैं जबकि सरकार सदन में दावा करती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है लेकिन सीमा पार से हमारे नौजवानों पर हमला हो रहा है, जानें जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा।

पुलिस कांस्टेबल की मृत्यु के बारे में बोलते हुए पायलट ने कहा कि बजरी के मामले में सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, अगर कोई गैरकानूनी काम हो रहा है, सरकार और प्रशासन इससे अगर सख्ती से नहीं निपटेगी तो अपराधियों का साहस बढ़ेगा। ऐसी घटनाओं (हेड कॉन्स्टेबल को टक्कर मारने जैसी घटना) से लोगों का मनोबल टूटता है। यह नौजवान पुलिस में काम करता था, पूरी पुलिस फोर्स का मनोबल टूटेगा। मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं कि सारी बातें छोड़कर अगर गैरकानूनी गतिविधिया कहीं हो रही हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग सदन के अंदर और बाहर मांग रखेंगे कि कोई भी अवैध कार्रवाई हो, कोई कितना

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- लोकार्पण के अवसर पर पायलट ने कहा, कि सरकार या जनप्रतिनिधि या किसी के भी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी पैसा व्यय किया जाता है, एक प्रकार का निवेश है।
- पायलट ने पुलिसकर्मी खुशीराम बैरवा के घर पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, कि बजरी के मामले में सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो प्रशासन और सरकार इससे अगर सख्ती से नहीं निपटेंगे तो अपराधियों में साहस बढ़ेगा। ऐसी घटनाओं (हैड कान्स्टेबल को टक्कर मारने जैसी) से लोगों का मनोबल टूटता है। यह नौजवान पुलिस में काम करता था, पूरी पुलिस फोर्स का मनोबल टूटेगा।
- उन्होंने इस संदर्भ में यह भी कहा कि हम लोग सदन के अंदर और बाहर मांग रखेंगे कि कोई भी अवैध कार्यवाही हो, कितना भी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके कहने पर अगर सरकार आँख मूँद लेगी और यह गैर कानूनी कार्यवाही होती रहेगी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

टोंक विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बजरी माफिया के ट्रक से कुचलकर मारे गये कॉन्स्टेबल खुशीराम बैरवा के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पायलट ने मृतक कॉन्स्टेबल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।